श्रादिम जातियों के तथा कितने श्रन्य जातियों के हैं ?

प्रधान मंत्री, प्रशु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) गोरखपूर, उत्तर प्रदेश में इस समय योजना भायोग का कोई कार्यालय नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लंदन में मारतीय उच्चायोग

10090. श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के ग्रधिकतर कर्मचारी भारत के स्वतंत्र होने से पहले से वहां पर कार्य कर रहे हैं भीर उनकी सेवा की शर्ते "ब्रिटिश राजकोष नियमों" द्वारा विनियमित होती हैं, न कि भारतीय भसैनिक सेवा के नियमों द्वारा,-जब कि वे नए कर्मचारी, जो भारत से वहां गये हैं, भारतीय सेवा के नियमों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं;
- (ख) क्या यह सच है कि दो प्रकार के इन नियमों के कारएा ''ब्रिटिश राजकोष नियमों" के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में मधिक लाभ तथा सुविधायें मिलती हैं;
- (ग) क्या यह भी सच है कि उन भारतीय कर्मचारियों को, जिन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार कर ली है, भीर जो ''ब्रिटिश राजकोष नियमों" के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं पौड़ों में पेंशन दी जायेगी; श्रीर
- (घ) यदि हां, तो वहां पर दो प्रकार के नियम रखने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, झखु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) ग्रीर (ख). यह सच है कि यनाइटेड किंगडम स्थित भारतीय हाई कमीशन में ऐसे बहत से कर्मचारो हैं जो भारत सरकार

की सेवा में वहां स्वतंत्रता से पहले से ही हैं। इन कर्मचारियों की नौकरी की शतें ब्रिटिश ट्रेजरी नियमों के यथानुरूप होती है इनके श्रलावा, वहां पर भारत-ग्रास्थानी ग्रधिकारी भीर कर्मचारी भी हैं जिनकी नौकरी की शर्ते पूरी तरह भारतीय सेवा नियमों के अनुरूप होती हैं। कार्यालयी वर्गों में स्थानीय कर्मचारियों का एक ग्रीर वर्गभी है जिसकी नौकरी की शर्ते एक खास स्कीम के अनुरूप होती हैं जिसे ''लंदन लोकल काडर स्कीम'' कहते हैं जिसमें वेतनमान और भत्ते रुपये में होते हैं; यह स्कीम म्रनिवायतः किफायत की दृष्टि से 1-4-63 से लागू की गई थी। यह सच है कि ब्रिटिश टेजरी नियमों के ग्रन्तगंत ग्राने वालों को रुपये वेतन-मान में "लंदन लोकल काडर" में काम करने वालों के मुकावले ज्यादा लाभ ग्रौर सुविधायें मिलती हैं। इस दूसरे वर्ग के कर्म-चारियों के भविष्य के बारे में जांच की जा रही है।

- '(ग) स्थानीय कर्मचारियों को पेंशन उन की राष्ट्रिकता के स्रनुसार नहीं दी जाती। सभी स्थानीय कर्मचारियों को सेवा-निवत्ति लाभ, भगर दिया जा सकता हो तो, पौंड स्टॉलिंग में दिया जाता है, उनकी राष्ट्रिकता चाहे कुछ भी क्यों न हो।
- (घ) जैसा की ऊपर बताया जा चुका है, इस हाई कमीशन में कर्मचारियों के तीन वर्ग हैं ग्रीर बदलती हुई परिस्थितियों के काररा यह ग्रपरिहार्य था।

Bugging of Confidential Discussions at UNCTAD

10091. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news items in London "Times" of the 15th March 1968 with "Delhi, March 14" date line to the effect that a serious diplomatic dispute has developed behind the scenes at UNCTAD Conference because of the suspected attempt

2750

at "bugging" of confidential discussions among the industrial nations of the West by under developed countries;

- (b) if so, whether any formal or informal protest have been launched; and
- (c) the reaction of Government to the news item and the protests referred to in part (b) above?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes, Sir.

- (b) The item in the London "Times" was factually incorrect and the UNCTAD Secretariat, through Press Note No. 6 dt. 18 March 1968, a copy of which is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—1226/68] denied that there had been any bugging.
- (c) Government feel that the issue was between the newpaper concerned and the UNCTAD Secre tarlat and in view of the latter's denial, no further action was considered necessary.

Yugoslavia's Stand on Nuclear Non-proli feration Treaty

10092. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: SHRI DEIVEEKAN: SHRI ANBUCHEZHIAN:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that President Tito of Yugoslavia has written to Indian Government about Yugoslavia's stand on the nuclear non-proliferation Treaty;
 - (b) if so, the details thereof; and
 - (c) the reaction of Government thereto?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Prime Minister's Visit to Sikkim and Bhutan

10093. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime

Minister propose to visit Sikkim and Bhutan; and

(b) if so, the specific reasons therefor in view of the fact that the Deputy Prime Minister has recently visited those places?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Yes, Sir. The Prime Minister visited Bhutan and Sikkim between 3rd May and 6th May on a goodwill visit in response to invitations received by her from the rulers of these two States.

Resignation of Chairman, Press Council

10094. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Chairman of the Press Council has sent his resignation to the Prime Minister;
- (b) if so, what are his allegations against Government;
- (c) whether it is also a fact that the Chairman has ojected to the setting up of the Advisory Committee of Members of Parliament on the Press Council; and
- (d) if so, Governments' reaction thereto?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). In his letter to the Prime Minister Shri J. R. Mudholkar had commented on the circumstances leading to the setting up of the Advisory Committee on the Press Council and regarding the committee. The resignation of Shri Mudholkar has been accepted by Government with effect from the 1st March, 1968. He has been invited to express his views before the Advisory Committee on its next meeting.

Documentary on Tribal India

10095. SHRI KARTIK ORAON:
Will the Minister of INFORMATION
AND BROADCASTING be pleased to
state:

(a) whether Government have any